

WEEKLY MEDIA UPDATE

(This document comprises news clips from various media in which BalmerLawrie is mentioned, news related to GOI and PSEs, and news from the verticals that we do business in. This will be e-mailed on every Monday.)

“Inauguration of Library cum reading room at Silvassa as a part of CSR initiatives” - received coverage in local papers on 19.11.2014

जिला अधिकारी जी. एस. मीणा ने खडोली में पुस्तकालय एवं वाचनालय का किया उद्घाटन



सिलवासा 18 नवंबर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के प्रशासन द्वारा चलाये गये कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अभियान का प्रमुख हिस्सा बनते हुए फात सरकार अंडर टेकिंग कंपनी बामर लारी कंपनी ने खडोली में कई बड़े सामाजिक कार्यों को पूरा करके कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी अभियान के तहत आज बामर लारी कंपनी द्वारा स्वयं सेवी संस्था रोटररी क्लब के सहयोग से बनाये गये पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन सरोहर आयोजित किया गया। दानह जिला अधिकारी जी. एस. मीणा ने इस पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित किया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खडोली में स्थित भारत सरकार की अंडर टेकिंग कंपनी बामर एंड लारी

कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत खडोली गाँव को गोद लिया हुआ था और इसी अभियान के तहत खडोली गाँव को माडल विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। जिसके तहत गाँव में सामुदायिक भवन, स्कूल भवन और प्रत्येक घरों में शौचालय उपलब्ध कराया था। इसी कार्यक्रम के तहत खडोली गाँव के लोगों को आधुनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय कंपनी ने बनाया। आज पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन कर खडोली की जनता को समर्पित करते हुए दानह के जिला अधिकारी जी. एस. मीणा ने कहा कि बामर लारी कंपनी ने रोटररी क्लब के साथ मिलकर जिस तरह से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है वह तारीफ के काबिल है और अगर इसी तरह दूसरी कंपनियां

भी आगे आकर सामाजिक क्षेत्र में काम करती है तो प्रत्येक गाँव को बड़े ही आसानी से आदर्श गाँव बनाया जा सकता है। इस अवसर पर खडोली माडल विलेज प्रोजेक्ट के चेयरमैन डॉ. विजय परमार ने बताया कि पुस्तकालय के साथ-साथ कंपनी द्वारा ऐसे बच्चों के लिए वाचनालय भी बनाया गया है जो अपने घरों में पढ़ाई करने नहीं कर पाते हैं वे अपनी किताबों के साथ इस वाचनालय में आकर बड़े आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इस अवसर पर दानह जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर वाघमारे, आंबोली जिला पंचायत सदस्य सोमा कडु, कंपनी के सैनिटरी वी.पी. एचआर रतन शेखर, वी. आर. रायमन के अलावा रोटररी क्लब के अध्यक्ष धर्मेश सिंह चौहान, सचिव विरल सिंह राजपुत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

Asli Azadi Dainik

खडोली के स्कूल में पुस्तकालय का कलेक्टर ने किया शुभारंभ



डॉन ऑफ इंडिया- सिलवासा 18-नवंबर-14: खडोली स्थित प्राथमिक गुजराती विद्यालय में बॉम्बे लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा रोटररी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा नवनिर्मित पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष का उद्घाटन दानह समाहर्ता जी.एस.मीणा के हाथों किया गया। इस अवसर पर जि.पं. अध्यक्ष शंकर वाघमारे, कंपनी के मानव संसाधन विभाग के ए.रत्नशेखर, रोटररी क्लब के प्रतिनिधि एवं स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य अग्रणी उपस्थित थे। समाहर्ता ने फाता काटकर अध्ययन कक्ष एवं पुस्तकालय का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सभी ने इस पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कंपनी द्वारा सी.आर. सी. स्कीम के तहत उपलब्ध

कराये गये इस सुविधा से छात्रों को काफी लाभ होगा। पुस्तकालय में वर्तमान समय में हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें रखी गयी है और आगामी दिनों में छात्रों एवं लोगों की रुचि के अनुसार और भी पुस्तकें रखी जायेंगी। लाईब्रेरी में चार टेबल लगाये गये हैं तथा यहां पर बैठने की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस अवसर पर

कलेक्टर जी.एस.मीणा ने बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा रोटररी क्लब ऑफ सिलवासा के इस प्रयास को सराहनीय बताया। उस दौरान कंपनी के प्रतिनिधि ए.रत्नशेखर ने बताया कि कंपनी द्वारा इससे पूर्व में भी आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों में वाटर ड्रिंटमेंट प्लांट एवं टॉयलेट्स बनाये गये हैं और हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है।

Dawn of India

खडोली स्कूल के पुस्तकालय का शुभारंभ



जनसंसार संवाददाता सिलवासा, 18 नवंबर संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के खडोली स्थित प्राथमिक गुजराती विद्यालय में बॉम्बे लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा रोटररी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा निर्मित पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। दानह जिला समाहर्ता जी.एस.मीणा ने इसे फाता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर जिला

पंचायत अध्यक्ष शंकर वाघमारे, कंपनी के मानव संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष ए.रत्नशेखर, रोटररी क्लब के प्रतिनिधि एवं स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य लोग मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने उद्घाटन के बाद पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। कंपनी द्वारा सीआरसी स्कीम के तहत उपलब्ध कराये गये इस सुविधा से बच्चों को काफी लाभ होगा। पुस्तकालय में हिन्दी, गुजराती

एवं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें रखी गयी हैं और आगामी दिनों में बच्चों को पुस्तकें रखी जायेंगी। लाईब्रेरी में चार टेबल लगाये गये हैं तथा यहां पर बैठने की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। कलेक्टर जी.एस.मीणा ने बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा रोटररी क्लब ऑफ सिलवासा के प्रयास को सराहनीय बताया है।

Sangh Pradesh Nav Bharat Plus

प्राथमिक स्कूल में क्लासरूम- लाइब्रेरी का शुभारंभ



सिलवासा, सं. खडोली स्थित प्राथमिक गुजराती स्कूल में बॉम्बे लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा रोटररी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा निर्मित पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष का शुभारंभ किया गया। जिसका उद्घाटन दानह जिला समाहर्ता जी.एस. मीणा द्वारा किया गया।

विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस अवसर पर जि.पं. अध्यक्ष शंकर वाघमारे, कंपनी के मानव संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष ए.रत्नशेखर, विजय परमार, रोटररी क्लब के प्रतिनिधि एवं स्कूल के प्राचार्य सहित शिक्षक एवं अन्य उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर ने फाता काटकर अध्ययन कक्ष एवं पुस्तकालय का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सभी ने इस पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। कंपनी द्वारा सी.आर.सी. स्कीम के तहत उपलब्ध कराये गये इस सुविधा से बच्चों को काफी लाभ होगा। पुस्तकालय में वर्तमान समय में हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें रखी गयी है।

Nishpaksh Jansatta

Leader Speak - Mr. Viren Sinha, Chairman and Managing Director Balmer Lawrie & Co. Ltd

Replying to Anil Mascarenhas of IIFL, Viren Sinha says, "The logistics business is the bottomline driver for the company and in the next 2-3 years we would be making investments of around Rs 350 crore in this business."

There are immense opportunities for growth in the area of cold chain logistics, 3PL, Project Logistics and Freight Forwarding. We are foraying into the areas of Cold Chain Logistics and Multi Modal Logistics Hub (MMLH). We are in the process of setting up multi product Temperature Controlled Warehouses (TCW), which will primarily cater to Quick Service Retail (QSR), Multi Retail (MR), Pharma and F&V segments of the market. We are also setting up a first of its kind MMLH at Visakhapatnam in association with Visakhapatnam Port Trust (VPT). We've made significant investments and we are fully geared up to grow this business in future.

India Infoline - 18.11.2014

http://www.indiainfoline.com/article/news-top-story/mr-viren-sinha-chairman-and-managing-director-balmer-lawrie-co-ltd-114111800159_1.html

Labour unions protest in one voice closure of sick PSU

Central trade unions of all hues are united in their opposition to the proposed closure of so-called sick PSUs as well as the Government's move to disinvest its stake in some profit-making undertakings.

They argue that if the Government has the will, there is still a lot of scope to revive or diversify these units and save thousands of jobs and prime assets, such as land. A nationwide strike will be observed by the trade unions on December 5 against the proposed closure of sick PSUs, among others. "This is an ill-intentioned government. They have taken a unilateral decision without giving due consideration to all dimensions of the matter," said Vrijesh Upadhyay, General Secretary of the BJP-backed Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS).

The Hindu Business Line - 21.11.2014

<http://www.thehindubusinessline.com/news/labour-unions-protest-in-one-voice-closure-of-sick-psus/article6622375.ece>

Govt plan to improve PSUs important for disinvestment, says Kotak

Longer term plan to improve performance of public sector undertakings (PSUs) is important for the government's divestment plan, Kotak has said in a report.

"In our view, the government may want to review its very ownership of PSU companies with a far bolder program of privatisation," the home-grown financial services major said in its note. The government aims to raise US \$9.5 billion via stake sale in state-run companies (or privatisation) in the current 2014-15 financial year to help plug its fiscal deficit. Kotak added that piece-meal divestments would achieve little in terms of improving efficiency and returns for the government. The financial services provider also said that the government's move to convert assets into income to meet current expenditure, without any consideration about the future will not be a good sign

Business Today - 20.11.2014

<http://businesstoday.intoday.in/story/kotak-mahindra-on-govt-disinvestment-plan-psu-ownership/1/212513.html>

Steel and Mines CPSUs to spend Rs 100 Cr on 2500 toilet blocks

A review meeting was held under the Chairmanship of Minister of Steel and Mines Shri Narendra Singh Tomar, with Heads of Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Steel and Ministry of Mines, at New Delhi on 19.11.2014

The meeting was attended by the Secretary Ministry of Steel, Shri Rakesh Singh, the Secretary Ministry of Mines, Dr. Anup K. Pujari along with other senior officers of both the Ministries. CMDs of all CPSEs viz, SAIL, RINL, MOIL, NALCO, MECL, HCL, MSTC, KIOCL, HSCL, MECON were present. While reviewing the progress of Swachh Bharat Abhiyaan, Shri Tomar advised the CPSEs to ensure that the identification & blocking of schools and placement of work orders must be completed by December'2014 and the construction of schools should be completed by March 2015.

Indiacsr.in - 21.11.2014

<http://www.indiacsr.in/en/steel-and-mines-cpsus-to-spend-rs-100-cr-on-2500-toilet-blocks/>

Govt hurries 40k cr stake sale in Coal India, ONGC

Narendra Modi led NDA Government is hurrying to mop up around Rs 40,000 crore through divestment of minority stakes in Coal India and ONGC before global investors go on year-end holidays.

Both state run behemoths have started road shows leading to a possible sell down within three weeks, at a slight discount to prevailing stock price, people directly involved with the matter said. Coal India's 10% share sale is likely to hit the markets by end this month, making government richer by Rs 22,250 crore. ONGC's 5% stake sale in early December may put about Rs 17,000 crore in government coffers. ONGC share sale may be slightly bigger depending on the investor response, sources added.

The Times of India - 19.11.2014

<http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Govt-hurries-40k-cr-stake-sale-in-Coal-India-ONGC/articleshow/45197182.cms>

After ONGC case fallout, OilMin tells PSUs not to drag govt to court

The petroleum ministry plans to issue an order to all its public sector undertakings not to file court cases against the government following a writ petition last May by Oil & Natural Gas Corporation charging the ministry of "acts of omission and commission" in an alleged theft of ONGC's natural gas by Reliance Industries Ltd. "Suitable instructions may be issued to Central PSUs under this ministry, so that such an eventuality viz CPSUs under the ministry having to file a court case against the ministry (itself alleging non-performance) may not arise in future..." additional secretary Rajive Kumar proposed last month. The step was later approved by petroleum minister Dharmendra Pradhan.

The Indian Express - 22.11.2014

<http://indianexpress.com/article/business/economy/after-ongc-case-fallout-oilmin-tells-psus-not-to-drag-govt-to-court/>

Shell wins transfer price case

The income-tax department today suffered another setback when the Bombay high court ruled in favour of the Indian arm of Royal Dutch Shell in a transfer pricing dispute.

It comes a little over a month after a division bench of the same court had ruled that telecom major Vodafone was not liable to pay an income tax of Rs 3,200 crore in another transfer pricing case.

Transfer pricing relates to transactions between two entities within the same group - usually

ONGC sets sights on New Zealand block

ONGC Videsh, the overseas arm of the state-owned explorer, has bid for an oil and gas block in New Zealand as part of the country's energy security strategy.

New Zealand had offered eight onshore and offshore blocks covering more than 190,000 square km in its latest licensing round. The bids had closed in September. In an investor presentation, Oil and Natural Gas Corporation said OVL "has submitted bid for New Zealand exploration block". However, it did not identify the block. Industry sources said the company had bid for an exploration block in the Taranaki offshore basin. This is OVL's maiden bid for an exploration acreage in New Zealand.

The Telegraph - 19.11.2014

http://www.telegraphindia.com/1141120/jsp/business/story_19063007.jsp#.VHKzUNKUdQc

India's crude oil refinery output jumps 4.2% in October 2014

Overall capacity utilization was higher at 104.65% during October 2014. India's crude oil refinery output rebounded 4.2% to 19.115 million tonnes (mt) in October 2014, snapping decline for last three sequential months. Public sector refineries recorded 1.9% growth in the output to 9.915 mt in October 2014. Meanwhile, the output of private refineries improved 1.4% to 7.723 mt, while that of Public-private joint venture refiner's surged 48% to 1.478 mt in October 2014 over October 2013.

Business Standard - 21.11.2014

http://www.business-standard.com/article/news-cm/india-s-crude-oil-refinery-output-jumps-4-2-in-october-2014-114112101256_1.html

Major ports to form company for last-mile connectivity

To put port connectivity works on a fast track, 12 Indian ports will pool the resources to set up a new company. The Union government is set to clear a proposal for creation of a Port Infrastructure Vikas Nigam Ltd. The company will construct, operate and maintain rail and road infrastructure to facilitate connectivity for transportation of goods from ports in India or abroad. The Union shipping ministry is in the process of seeking Cabinet approval for this.

located in two different countries. A dispute over transfer pricing arises when the authorities suspect that the deal hasn't occurred at an arm's length basis, whereby commercial considerations have been undermined because of preferential treatment extended to a group entity.

The Telegraph - 19.11.2014

http://www.telegraphindia.com/1141119/jsp/business/story_1745.jsp#.VHLZKdKUdQc

Logistics companies looking for funds to build scale & be GST-ready

An expected roll out of Goods and Service Tax (GST) is pushing privately-held logistics companies to look for funds from private equity firms, strategic investors and public listing in order to finance massive expansion in warehouses and fleet. The logistics sector will see a slew of deals in the next one year as international and domestic investors scout for targets, while companies look to unlock value.

Experts say larger companies in will look at a public listing while mid-sized companies will seek strategic or PE funding. Mahindra Logistics and TVS Logistics may rope in institutional investors, which have a shorter timeline than PE firms, are showing interest. "It is true that investor interest has gone up in the past few months. GST is forcing large consolidation in the sector," said TVS Logistics Managing Director R Dinesh. "We will start thinking of an IPO in about a year," added Dinesh, who is also co-chairman of CII's Institute of Logistics Advisory Council. Mahindra Logistics, backed by Kedaara Capital, is scaling up through acquisitions before getting listed. TVS has an annual revenue of Rs 2,500 crore, while Mahindra makes Rs 1,750 in topline.

The Economic Times - 20.11.2014

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11-20/news/56304190_1_logistics-companies-snowman-logistics-mahindra-logistics

Govt plans big push for coastal shipping

For a country that boasts of an expansive coastline of 7,500 kilometres, coastal shipping plays a surprisingly small role, transporting a little over 160 million tonnes (mt) of cargo in 2012-13, in the domestic movement of goods. To rectify this imbalance, the government is mulling over a scheme to promote coastal shipping.

According to the proposed plan, a subsidy of Rs 0.5 per tonne per km on bulk cargo, a rebate of Rs 2,000 per container for container cargo and an additional 20 per cent rebate on vessel/cargo-related charges would be offered. The subsidy would be provided directly to shippers of general

According to documents reviewed by Business Standard, the company's paid-up capital will be Rs 50 crore, with equity participation from the 12 major port trusts. The authorised share capital will be around Rs 100 crore, divided into a million equity shares of Rs 1,000 each.

Business Standard - 24.11.2014

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/major-ports-to-form-company-for-last-mile-connectivity-114112400018_1.html

Need to free major ports from tariff regulation: Jawahar Lal Nehru Port Trust Chief

Regulation of tariffs at major ports is inhibiting their growth and there is a need to free them for better price parity with non-major ports, a top official said here today. "Tariff Authority for Major Ports (TAMP) regime inhibited the growth of major ports and there is a need to free them from the regulatory regime for better price parity and create a level-playing field to compete with fast expanding non-major ports," Jawahar Lal Nehru Port Trust (JNPT) Chairman N N Kumar said here today.

Addressing a meeting organised by industry body Ficci on the Ports and Shipping sector, Kumar said there is no need for regulation of tariff rates at major ports. JNPT is among the 12 major ports in the country. On public-private-partnership (PPP) projects in the sector, he said that in the absence of a mechanism to revisit port concession agreements, private players felt discouraged to participate in such schemes.

The Economic Times - 17.11.2014

<http://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/shipping/-transport/need-to-free-major-ports-from-tariff-regulation-jawahar-lal-nehru-port-trustchief/articleshow/45179179.cms>

PE and foreign funds rush to agri-logistics

Private equity players and foreign funds have been showing strong interest in the infrastructure and logistics space in the six months since the new government came to power. Agri-logistics, warehousing and private freight terminals have been areas, where there have been a lot of deal activities of late.

Some of the prominent deals in the logistics space in recent times included Mandala Capital's Rs 150 crore investment in Gati Kauser, Temasek's Rs 250 crore investment in Star Agri and Taro Capital's Rs 80 crore

cargo items like salt, sugar, automobiles, fertilisers, tiles, steel, cement, marble and foodgrain. A similar subsidy scheme, offering a subsidy of Rs 1 a tonne per km, was previously announced by the Kerala government, which is yet to take off.

Business Standard - 18.11.2014

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-plans-big-push-for-coastal-shipping-114111801039_1.html

SAARC Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States

The Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the Signing and ratifying the SAARC Motor Vehicles Agreement at the SAARC summit on November 26-27, 2014 in Kathmandu. Further, the Cabinet approved the signing of a Bilateral Agreement for the regulation of passenger traffic between Government of India and Republic of Nepal on the sidelines of the forthcoming SAARC Summit in Kathmandu. The Cabinet has also authorized the Ministry of Road Transport & Highways to sign similar Bilateral Agreements and Protocols with other SAARC member States.

Business Standard - 20.11.2014

http://www.business-standard.com/article/government-press-release/saarc-motor-vehicle-agreement-for-the-regulation-of-passenger-and-cargo-114112001425_1.html

Domestic air traffic rises 18.31% in October

Domestic air traffic grew by over 18 per cent last month compared to October last year as Air India's passenger load factor overshoot that of IndiGo which had the largest number of flight cancellations, official data showed on Monday.

Domestic airlines flew 59.25 lakh passengers in October this year registering a growth of 18.31 per cent over the 50.08 lakh passengers flown during the same period in the previous year, the latest data released by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) showed.

Business Today - 17.11.2014

<http://businesstoday.intoday.in/story/domestic-air-traffic-air-india-express-air-costa-october/1/212464.html>

investment in Shri Shubham Logistics, a group company of Kal-pataru. "There is a good level of interest in niche segments within the logistics sector, such as cold chain, agri-logistics, warehousing and private freight terminals," said Manish Saigal, MD of Alvarez and Marsal, a global consulting firm.

Financial Chronicle - 24.11.2014

<http://www.mydigitalfc.com/news/pe-and-foreign-funds-rush-agri-logistics-625>

We want to double ports' capacity, divert transport to inland waterways: Nitin Gadkari

The government is banking on the infrastructure sector, which needs huge capital inflows, to help steer the economy back in the direction of high growth figures. Union minister of road transport, highways and shipping, Nitin Gadkari, tells HT that a cut in lending rates is the need of the hour. For success of the PPP (public-private partnership) model it is important that the lending rates are cut. Worldwide the interest rate is between 2-3%. But in our country it is between 12% and 13%. It is economically not viable. So if we want to make a success story we need to reduce our interest rate. I have requested the finance minister to consider this and he is trying his level best to see how it can be done.

The Hindustan Times - 21.11.2014

<http://www.hindustantimes.com/india-news/we-want-to-double-ports-capacity-divert-transport-to-inland-waterways-nitin-gadkari/article1-1288763.aspx>

Online portals reduce losses on improved margins

India's top three travel portals continue to remain in the red but the losses shrank in 2013-14 over the previous year, due to an improvement in margins. Nasdaq-listed MakeMyTrip reduced its net loss to \$20.9 million (about Rs 125 crore) in FY14 from \$27.6 mn (Rs 165 crore) in FY 13. Cleartrip and Yatra.com, both unlisted, halved their loss to Rs 40 crore in the same period. Together, the three companies dominate the online travel space in India, with a combined market share of a little over 87 per cent. MakeMyTrip has 47 per cent, while Cleartrip and Yatra's is about 20 per cent each.

Business Standard - 18.11.2014

http://www.business-standard.com/article/companies/online-portals-reduce-losses-on-improved-margins-114111800954_1.html

Online Travel Dominates Tourism Market In India

Smartphones have tangibly changed the way world operated before their arrival. Earlier, when the market operated through Internet connection on personal computers, things were a tad bit slow since that category came from a different class altogether. But today, things are available at a cursory glance, and literally at fingertips. All the best things are happening on the Internet, and guess what they are ensuring—is that consumer is truly the king of the market!

An average Indian earlier travelled within the confines of his country, and those travels were mostly to relatives or to places of religious/spiritual importance. But today, an average Indian is well-travelled, adequately informed about different cultures and has a huge appetite for adventure tourism; no matter what it involves.

Business Insider - 20.11.2014

<http://www.businessinsider.in/Online-Travel-Dominates-Tourism-Market-In-India/articleshow/45215838.cms>

CIL to get new boss

Coal India today got a new chairman and managing director after a gap of almost five months. Sutirtha Bhattacharya, chairman and managing director of Singareni Collieries Company Limited, was selected for the post by the Public Enterprise Selection Board under the ministry of personnel, public grievances and pension.

The Telegraph - 18.11.2014

http://www.telegraphindia.com/1141119/jsp/business/story_1741.jsp#.VG7BdyOUdQc

New rules may let domestic carriers fly abroad sans curbs

The civil aviation ministry is looking to scrap restrictions on Indian carriers that want to start overseas services, a move that will benefit new entrants such as

Tata-SIA joint venture Vistara but may displease existing airlines IndiGo, Jet Airways and others. "You have limited them by laws like 5/20," civil aviation minister Ashok Gajapati Raju Pusapati said in an interview, referring to the rule that Indian carriers should have been flying for five years and have 20 planes to be eligible for starting overseas operations. "Allow them. Indians are capable people and they have proved this off and on." He likened the norm to a "reservation kind of a system" that keeps small players out and said the ministry was developing a formula to replace the eligibility rule.

The Economic Times - 24.11.2014

<http://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines/-aviation/new-rules-may-let-domestic-carriers-fly-abroad-sans-curbs/articleshow/45253289.cms>

Neeraj Kuamr selected as Director (Fin), IFFC

PSEB has recommended the name of Shri Neeraj Kumar, GM, PFC, for the post of Director (Finance), Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) at a Public Enterprises Selection Board meeting held on November 20, 2014. Total 13 persons were appeared in the interview

pseb.nic.in - 21.11.2014

www.pseb.nic.in